GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF JAL SHAKTI,

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *138

ANSWERED ON 02.08.2021

CONSTRUCTION OF A DAM FOR IRRIGATION AT NARSINGHPUR, M.P.

***138 SHRI KAILASH SONI**

Will the Minister of ***JAL SHAKTI*** be pleased to state:

(a) the status of the construction of a dam for proposed Small Irrigation Scheme under the Babai Chichali development block of Narsinghpur district at Madhya Pradesh (M.P.);

(b) by when the work would start; and

(c) the reasons for not starting the work?

ANSWER

THE MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (C) OF STARRED QUESTION No. *138 TO BE ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 02.08.2021 REGARDING "CONSTRUCTION OF A DAM FOR IRRIGATION AT NARSINGHPUR, M.P." BY SHRI KAILASH SONI

(a) to (c) Irrigation projects are planned, implemented and managed by the concerned State Governments, as per their own resources and priorities. Role of Government of India is limited to providing technical support, and partial financial support in some cases, as per the norms of the existing schemes being implemented by Government of India. Though techno-economic viability for the Major and Medium Irrigation projects on inter-state river systems is to be appraised by Central Water Commission (CWC) under Ministry of Jal Shakti, for minor irrigation schemes this mandate also lies with the State Governments themselves.

Water Resources Department (WRD) and Narmada Valley Development Authority (NVDA), Government of Madhya Pradesh, have informed that currently, no such dam for small irrigation scheme is being constructed or proposed in Babai or Chichali development blocks of Narsinghpur district at Madhya Pradesh.

NWDA has, however, informed that a major project, namely Shakkar Pench Link Joint Project on river Shakkar near Hathnapur village in Narsinghpur District of Madhya Pradesh, is at planning stage. The project envisages irrigation of 95,839 ha of land through pressurised pipe system, by creating a storage of 370.47 million Cubic Meters (MCM). The proposed command of the project includes Chichali and Saikhera development blocks of Narsinghpur District, and Amarwada development block of Chhindwada District of Madhya Pradesh.

It is further informed by NVDA that the project was approved by the State Government in May, 2020 for an estimated cost of Rs. 3,381.80 crore at 2017 price level. Thereafter, in March, 2021, the cost of the project has been revised to Rs. 4,434.02 crore, with updation of price level and also inclusion of some additional components.

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *138

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

.....

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण

***138. श्री कैलाश सोनी:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बाबई चीचली विकास खंड के अंतर्गत प्रस्तावित लघु सिंचाई योजना के लिए बांध के निर्माण की स्थिति क्या है;

(ख) यह कार्य कब तक प्रारंभ होगा; और

(ग) इस कार्य के प्रारंभ न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण" के संबंध में श्री कैलाश सोनी द्वारा दिनांक 02.08.2021 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *138 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की योजना, उनका कार्यान्वयन और प्रबंधन किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा योजनाओं की शर्तों के अनुसार तकनीकी सहायता, और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित होती है। यद्यपि, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा अंतर-राज्यीय नदी प्रणालियों पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाना होता है जबकि लघु सिंचाई योजनाओं का अधिकार स्वयं राज्य सरकारों के पास ही होता है।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), मध्य प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि मौजूदा समय में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बाबई या चीचली विकास खंडों में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत न तो किसी बांध का निर्माण किया जा रहा है न ही निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है।

हालांकि, एनवीडीए ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के हथनापुर गांव के पास शक्कर नदी पर शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना नाम से एक वृहद परियोजना, प्लानिंग स्टेज में है। परियोजना में 370.47 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) की भंडारण क्षमता तैयार करते हुए, दबावयुक्त पाइप प्रणाली (प्रैशराइज्ड पाईप सिस्टम) के माध्यम से 95,839 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि पर सिंचाई की परिकल्पना की गई है। परियोजना की प्रस्तावित कमान में नरसिंहपुर जिले के चीचली और साईखेड़ा विकास खंडों और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकास खंड शामिल हैं।

एनवीडीए द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने इस परियोजना को 3,381.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2017 के मूल्य स्तर पर मई, 2020 में अनुमोदित किया था। इसके बाद, मार्च, 2021 में, परियोजना लागत के मूल्य स्तर को अद्यतन करते हुए संशोधित करके 4,434.02 करोड़ रूपए कर दिया गया है और कुछ अतिरिक्त घटकों को भी शामिल किया गया है।

*****

श्री कैलाश सोनी : माननीय उपसभापति जी, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में बाबई चीचली विकास खंड के अंतर्गत प्रस्तावित लघु सिंचाई योजना के लिए बांध के निर्माण की स्थिति क्या है? ...(**व्यवधान**)...यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और इस कार्य के प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : उपसभापति जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का समुचित उत्तर लिखित में सभा पटल पर रखा गया है। ...(**व्यवधान**)... जल सम्बन्धी योजनाओं को भारत सरकार प्राथमिकता देती है। ...(**व्यवधान**)...जब किसी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास आता है तो हम उसके द्वारा डिजाइन करने का और इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं।...(**व्यवधान**)... मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वहां की राज्य सरकार की तरफ से नरसिंहपुर में किसी भी तरह का एसएमआई प्रोजेक्ट बनाए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार में किसी भी स्तर पर लम्बित नहीं है।...(**व्यवधान**)... इसके अतिरिक्त मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अपने लिखित उत्तर में भी कहा है। शक्कर पेंच लिंक जॉइंट प्रोजेक्ट जरूर नरसिंहपुर जिले में होने वाला है और वह प्रस्तावित है। ...(**व्यवधान**)... इस प्रोजेक्ट के ऊपर नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने revised cost estimate के साथ उसे नए price level के साथ उसे additional component include करते हुए उसके ऊपर विचार करने के लिए लिखा है।...(**व्यवधान**)...

श्री कैलाश सोनी : मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पन-बिजली भी प्रस्तावित है? ...(**व्यवधान**)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, अभी यह प्रोजेक्ट समीक्षा के स्तर पर नहीं आया है इसलिए इस बारे में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है। यह अभी डीपीआर स्टेज पर है। ...(**व्यवधान**)...जब डीपीआर बन जाएगी, उसके बाद मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे पाऊंगा।...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा : उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उनकी पहल के बाद से जल संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रयत्न किए हैं। ...(**व्यवधान**)...मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के tribal region में डेढ़ लाख छोटे-छोटे जल संरक्षण के परम्परागत डैम्स हैं।...(**व्यवधान**)... उन डैम्स को रिवाइव करके हम परम्परागत रूप से जल संरक्षण कर सकते हैं, खासकर बरसात के सीज़न में जो पानी आता है। ...(**व्यवधान**)...मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन परम्परागत डैम्स को रिवाइव करने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है और कितनी जल्दी उसे लागू किया जा सकता है? ...(**व्यवधान**)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में 2019 में सरकार बनने के बाद जल शक्ति अभियान लागू किया गया था। ...(**व्यवधान**)...देश के चुनिंदा 270 जिलों में, जहां पानी का स्तर सबसे ज्यादा चिंताजनक था, वहां यह योजना प्रारम्भ की गई थी। लेकिन इस वर्ष से हमने देश के 700 ही जिलों में इस योजना को प्रारम्भ किया है।...(**व्यवधान**)... साफ पानी का संकलन करना, उसे सहेजना, उसका संरक्षण करना और देश के लिए तथा देश की जनता की जल सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करना देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।...(**व्यवधान**)... मैं माननीय सदस्य का इस प्रश्न को उठाने के

लिए अभिनन्दन करना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में 15वें वित्त आयोग ने विभिन्न चर्चाओं के बाद जो धनराशि की अनुशंसा की है, उसका 30 प्रतिशत हिस्सा पानी के सम्बन्ध में जुड़ी हुई योजनाओं के लिए आरक्षित किया है।...(**व्यवधान**)... इसके अतिरिक्त 'मनरेगा' में भी इस कार्य के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाती है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप वैल में आकर इस तरह से संसदीय परम्पराओं के खिलाफ जाकर आसन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सवाल-जवाब चल रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : इस योजना में जल से सम्बन्धित जो कार्य होने चाहिए, उनकी सूची बनाई गई थी और हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में उसे शुरू किया है। ...(**व्यवधान**)...इस बारे में हमने राज्य सरकारों के साथ सारी सूची साझा भी की है। हमारा पूरा प्रयास है कि प्रत्येक स्थान पर अपेक्षित गतिविधियों को प्रस्तावित करके उन्हें पूरा किया जा सके।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 139, डा. फौजिया खान।